भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3664

दिनांक 03.04.2023 को उत्तर देने के लिए

एमडीजी के अंतर्गत एससी और एसटी हेतु निर्धारित लक्ष्य

3664. **श्रीमती फूलो देवी नेतम**:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एमडीजी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का राज्य-वार प्रदर्शन कैसा है; और

(घ) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान एमडीजी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसके परिणाम क्या रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन द्वारा निर्धारित वर्ष 2015 के लिए 18 मात्रात्मक लक्ष्यों के साथ आठ अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का एक सेट था। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण एक ही ढांचे के भीतर दुनिया के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर मापने योग्य लक्ष्यों और लक्ष्यों को स्थापित करने का पहला वैश्विक प्रयास था और

इससे मज़बूत देशों और समुदायों को कार्रवाई के लिए प्रेरणा मिली। आठ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित थे:

i. अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को खत्म करना;
ii. वैश्विक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना;
iii. महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना;
iv. बाल मृत्यु दर को कम करना;
v. मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना;
vi. मलेरिया, एचआईवी/एड्स और अन्य बीमारियों से लड़ना ;
vii. पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना; और
viii. विकास के लिए एक सार्वभौमिक साझेदारी विकसित करना।

वर्ष 2000 में एमडीजी को अपनाने के बाद से पंद्रह वर्ष की अवधि में विश्व में महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तन देखा गया है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, एमडीजी से सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) विकसित हुए। एसडीजी 17 लक्ष्यों और 169 संकेतकों का एक समूह है जिसका उद्देश्य 2030 तक किसी को पीछे न छोड़ते हुए मानव कल्याण की अधिकाधिक उपलब्धि के लिए विकास कार्यों को व्यवस्थित और कारगर बनाने में सहायता करना है। एसडीजी हमारे विश्व को बदलने का हिस्सा हैं: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, जिसे सितंबर 2015 में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया और 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ।

नीति आयोग को केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, नागरिक समाज संगठनों आदि को शामिल करते हुए एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए एसडीजी पर समन्वय कार्य का कार्य सौंपा गया है। नीति आयोग ने एसडीजी की प्रगति का अनुमान लगाने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स का निर्माण किया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार भारत के लक्ष्यवार प्रदर्शन को दर्शाने वाला एक **अनुलग्नक** में है।

*****

अनुलग्नक

श्रीमती फूलो देवी नेतम द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एमडीजी के तहत निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में दिनांक 03.04.2023 को उत्तर देने के लिए पूछे गये राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3664 का अनुलग्नक।

एसडीजी	**2020-21**
	अखिल भारत स्कोर (100 में से)
एसडीजी 1 - कोई गरीबी नहीं	60
एसडीजी 2 - भूखमरी समाप्त करना	47
एसडीजी 3 - अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती	74
एसडीजी 4 - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	57
एसडीजी 5 - महिलाओं के लिए समानता	48
एसडीजी 6 - स्वच्छ जल और स्वच्छता	83
एसडीजी 7 - वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा	92
एसडीजी 8 - अच्छा काम और आर्थिक विकास	61
एसडीजी 9 - उद्योग, नवाचार और अवसंरचना	55
SDG 10 - असमानताओं में कमी	67
एसडीजी 11 - सतत शहर और समुदाय	79
एसडीजी 12 - जिम्मेदार खपत और उत्पादन	74
एसडीजी 13 - क्लाइमेट एक्शन	54
एसडीजी 14 - पानी के नीचे जीवन	उपलब्ध नहीं
एसडीजी 15 - भूमि पर जीवन	66
एसडीजी 16 - शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं	74
समग्र स्कोर	**66**

*****